दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यु इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
CIN No. L66000MH1919GOI000526

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Phone : 022 2270 8100
022 2270 8400
Website : www.newindia.co.in

Ref. No.: NIACL/CMD_BoardSectt/2023-24

15th March, 2024

To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai 400 001

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor, Plot C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE – 540769/NSE – NIACL)

Dear Sir/Madam,

Sub: Extract of Notice of postal ballot and intimation of completion of dispatch published in Newspapers.

This has reference to our letter dated 14.03.2024 whereby we had submitted the Notice of Postal Ballot and completion of dispatch intimation.

The Newspaper clipping of the "Extract of Notice of postal ballot and intimation of completion of dispatch as published in Newspapers" is enclosed. The said extracts are also available on Company's website at www.newindia.co.in

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You
Yours faithfully

For The New India Assurance Company Limited

THE NEW INDIA ASSU. CO. LTD. H. O. MUMBAI

Jyoti Rawat
Company Secretary & Chief Compliance Officer

खबर कोना

होली में डीयू परिसर में हुड़दंग करने पर होगी कार्रवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 मार्च।

होली का त्योहार ही ऐसा है कि हर ओर रग के साथ होली की हुड़दंग देखने को मिलती है, लेकिन ये हुड़दग कई बार माहौल बनाने की बजाय बिगाड़ देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से साफ कहा गया है कि जो कोई होली के दौरान के गुंडागर्दी और अशांति फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीयू रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने बताया कि होली के चलते विशेष रूप से महिला छात्रों को निशाना न बनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही डीयू के दोनो परिसरो, छात्रावासो और कालेजों में विस्तृत आंतरिक व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में कदम उठाने की पहल शुरू कर दी गई है। हुड़दंग करने वालो पर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जामिया में तीन नए विभागों की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 मार्च।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अब तीन नए विभागो की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रपति ने जामिया के विजिटर के रूप में तीन नए विभागों के निर्माण के लिए मौजूदा कानून में संशोधन व परिवर्धन के लिए अपनी सहमति दी है। जिसके बाद विधि संकाय के अंतर्गत विधि विभाग, दंत चिकित्सा विज्ञान विभाग और चिकित्सा विज्ञान विभाग में दंत चिकित्सा संकाय बनाया जाएगा।

रामलीला मैदान में किसानों ने केंद्र के खिलाफ लगाए नारे, कहा

सरकार के खिलाफ तेज होगा प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 मार्च।

दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसान मजदूर महापंचायत में हजारों किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि क्षेत्र के संबंध में केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध तेज करने और आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान आंदोलन जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद 2021 में दिल्ली की सीमाओं पर उनका आंदोलन समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में किसानों का यह संभवतः सबसे बड़ा जमावड़ा था।

वर्ष 2021 के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों के प्रमुख निकाय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने खेती, खाद्य सुरक्षा, भूमि और लोगों की आजीविका को बचाने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। महापंचायत में भाग लेने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों की मांगों को वर्षों से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान भी अपना आंदोलन जारी रखने और भाजपा की नीतियों पर निशाना साधने का प्रस्ताव पारित किया। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कई महिला किसान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई।

महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से किसान आए थे।

सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमसे बात करनी चाहिए : टिकैत

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत ने बताया कि हमने बैठक की और सरकार को संदेश गया है कि हमारे देश के किसान एकजुट हैं। सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमसे बात करनी चाहिए। यह आंदोलन जल्द रुकने वाला नहीं है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को मजदूर बनाकर देश को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अलग-अलग किसान संघ बनाकर किसानों की एकता को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे हमें जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं।

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को 'किसान मजदूर महापंचायत के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर जाम में फंसे वाहन।

महापंचायत से दिल्ली की सड़कों पर जाम

नई दिल्ली, 14 मार्च (संवाददाता)।

रामलीला मैदान में गुरुवार को 'किसान मजदूर महापंचायत' के मद्देनजर मध्य दिल्ली और सराय काले खां में यातायात का बुरा हाल रहा। राजधानी में वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आइटीओ, दिल्ली गेट, दरियागंज और सराय काले खां के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-24 समेत विभिन्न स्थानों पर जाम लग गया। सराय काले खां में भारी भीषण जाम देखा गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि कुछ यात्रियों को कुछ जगहों पर कुछ परेशानी हुई होगी लेकिन आम तौर पर वाहनों की आवाजाही ठीक रही।

दिल्ली यातायात पुलिस ने एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यात्रियों को यातायात नियमों और मार्ग परिवर्तन के बारे में सचेत किया गया था। परामर्श के जरिए यातायात पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया था कि यदि संभव हो तो उपरोक्त सड़कों से जाने से बचें और सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवाओं का ज्यादा उपयोग करें।

गंगा और यमुना के बीच की भूमि पर दावा जताने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, 14 मार्च (भाषा)।

अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगरा से लेकर मेरठ तथा दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तराखंड की 65 राजस्व संपदाओं सहित अन्य स्थानों पर यमुना और गंगा के बीच की भूमि पर स्वामित्व का दावा करने वाले एक व्यक्ति की याचिका गुरुवार को एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए खारिज कर दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्ववर्ती राजा के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिंह ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आजादी के 75 साल बाद इस तरह का दावा नहीं कर सकता। एकल पीठ ने दिसंबर में सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने अपील में दावा किया था कि संयुक्त प्रांत आगरा के 'बेसवां परिवार की रियासत' के अंतर्गत आने वाली भूमि पर उनका हक है और चूंकि उनके पूर्वजों और भारत सरकार के बीच कोई अधिग्रहण समझौता नहीं हुआ था।

दिल्ली सरकार ने नौकरशाही में किया फेरबदल

निहारिका राय को किया कार्यमुक्त, नवीन चौधरी को तीन विभागों का प्रभार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 मार्च।

दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति आदेश जारी किया है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार, 1993 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) काडर के अधिकारी प्रशांत गोयल को प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन) नियुक्त किया गया है। इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं निहारिका राय को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

वर्ष 1994 बैच के आइएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को तीन सरकारी विभागों का प्रभार दिया गया है। उन्हें प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण) के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके पास प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन) सहित दो अतिरिक्त प्रभार भी होंगे। इसके अलावा, 2011 बैच की अधिकारी मिताली नामचूम निदेशक (महिला एवं बाल विकास) का कार्यभार संभालेंगी। कृष्ण कुमार को प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार दो अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) का प्रभार संभाल रहे थे। उनके पास उपायुक्त (मुख्यालय) समेत अन्य प्रभार रहेंगे।

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd.

पंजीकृत और प्रधान कार्यालय: 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001
सीआईएन क्र: एल66000एमएच1919जीओआय000526, आईआरडीएआई रजि. क्र.: 190
दूरभाष: +91 22 22708263; फैक्स: +91 22 22652811
ईमेल: investors@newindia.co.in ; वेबसाइट: www.newindia.co.in

डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और धारा 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, विनियम के 44 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015, और उसके तहत जारी किए गए अधिनियमों, नियमों, विनियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अन्य लागू प्रावधान (समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित), कंपनी ने:

ई-वोटिंग के लिए उन सदस्यों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एनएसडीएल के माध्यम से एक ईमेल भेजा गया, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कंपनी के साथ पंजीकृत किया है; उन सभी सदस्यों को, जिनका नाम 08 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है, नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान करना होगा। 1) कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन ताकि उस स्थिति को प्रतिबिंबित किया जा सके जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, 2) एओए में संशोधन - कार्यकारी निदेशक का पद शामिल करने के लिए।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान **गुरुवार, 21 मार्च, 2024 (भारतीय समयनुसार 9:00 पूर्वाह्न) से शुरू होगा और शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2024** (भारतीय समयनुसार 5:00 अपराह्न) को समाप्त होगा। सदस्य मतदान के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकल्प चुन सकते हैं।

निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र/ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री एस.एन. विश्वनाथन और उनके स्थान पर एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी की पार्टनर सुश्री मालती कुमार को संवीक्षक नियुक्त किया है।

सदस्यों के मतदान अधिकार **08 मार्च, 2024** को माने जाएंगे जो कि कट-ऑफ तारीख है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। पोस्टल बैलेट नोटिस की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.newindia.co.in पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया हमारी वेबसाइट www.newindia.co.in या www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध डाक मतपत्र के नोटिस के साथ संलग्न ई-वोटिंग के निर्देशों को देखें।

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो वे इसे अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें और यदि भौतिक रूप के शेयर उनके पास हैं तो मेसर्स लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत करें।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे श्री महेश मसुरकर, निवेशक संबंध, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी. एस.मार्ग, विक्रोली (डब्ल्यू), मुंबई - 400 083 से संपर्क करें। फ़ोन नंबर +91 22 49186270, ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in। इसके अलावा सदस्य सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, "ए" विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013, टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 /1800 224 430 से भी संपर्क कर सकते हैं।, ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए
एसडी/-
ज्योति रावत
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 14 मार्च, 2024

पाकीटबंद अन्न 'किडनी'साठी धोकादायक

आरोग्य वार्ता

नवी दिल्ली : चांगल्या आरोग्यासाठी तुमची किडनी निरोगी असणे खूप महत्त्वाचे आहे. बदलत्या खाण्याच्या सवयींमध्ये लोकांना पाकीटबंद अन्न (पॅकेज फूड) जास्त आवडत असल्याचे दिसून आले आहे. या अन्नातून पोट भरलेले वाटते. मात्र, हे अन्न सर्वात धोकादायक ठरत आहे. याचा थेट परिणाम हा किडनीवर होत असल्याचे एका संशोधन अहवालात समोर आले.

संशोधनानुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थानसह उत्तरेकडील लोक भरपूर अन्न खातात. पण पोषणाचा विचार करणे तर दूरच राहते. लोक प्रथिने, खनिजे आणि पोटॅशियमपासून इतके दूर आहेत की त्यांच्या किडनीवर विपरीत परिणाम होत आहे. देशातील सुमारे १७ टक्के लोक किडनीच्या आजाराने ग्रस्त आहेत.

उत्तर भारतातील बहुतेक कुटुंबांमध्ये मीठयुक्त पदार्थ ते भुजिया, पापड किंवा चिप्स असतात. या पदार्थांमुळे काही काळ चव मिळते, पण त्यातील मीठ आरोग्य बिघडवते. चंडीगडमधील जॉर्ज इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थने पीजीआय हॉस्पिटलच्या सहकार्याने संशोधन करण्यात आले. यामध्ये ४०० लोकांच्या रोजच्या आहाराचे विश्लेषण केले. यातील निम्मे लोक पूर्णपणे निरोगी होते. निम्म्या लोकांना किडनीचा काही ना काही आजार होता. निरोगी व्यक्तींनाही किडनी, रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका असतो.

स्वयंपुनर्विकासासाठी सवलत

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्कासाठी १० टक्के मूल्य; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

> शासकीय भूखंडावरील २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था हे मूल्य पाच टक्के करावे अशी मागणी करीत असताना त्यांना स्वयंपुनर्विकासाची अट घालणे योग्य नाही. एकाच राज्यात भूखंडाबाबत असा भेदभाव का? सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना सरसकट दोन टक्क्यांचा लाभ द्यायला हवा होता.
> – सलील रमेशचंद्र, शासकीय भूखंड विकसित झालेल्या संस्थेच्या महासंघाचे अध्यक्ष

मुंबई : राज्यातील शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (भोगवटादार दोनमधून धारणाधिकारी एकमध्ये रूपांतर) बहाल करण्यासाठी शीघ्रगणकाच्या (रेडी रेकनर) १५ टक्क्यांऐवजी दहा टक्के मूल्य आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारतील, त्यांना फक्त पाच टक्के मूल्य शासनाला अदा करावे लागणार आहे.

राज्यात २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, मुंबईत तीन हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार, वैयक्तिक भूखंडधारकांना रेडी रेकनरच्या २५ टक्के तर सहकारी संस्थांना रेडी रेकनरच्या १५ टक्के रक्कम भरून मालकी हक्क मिळणार होता. पाच वर्षांची मुदत ७ मार्चला संपुष्टात आली. त्यात आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, या काळात शहरातील वैयक्तिक भूखंडधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. शहरात फक्त एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने १५ टक्के मूल्य अदा करून मालकी हक्क मिळविला. या योजनेतून शासनाला ६४० कोटींचा महसूल मिळाला. उपनगरात मोठ्या संख्येने असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला नाही. हे मूल्य पाच टक्के करावे, अशी या सहकारी संस्थांची मागणी होती.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात हे मूल्य पाच टक्के केले जाईल, अशी घोषणाही केली. परंतु प्रत्यक्षात अधिसूचना जारी केली नाही. त्यामुळे हा निर्णय प्रलंबित राहिला होता. अखेरीस बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने निर्णय घेण्यात आला. स्वयंपुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांना पाच टक्के मूल्य भरून मालकी हक्क मिळविता येणार आहे. राज्यातील नजूल भूखंड रेडी रेकनरच्या दोन टक्के मूल्य आकारून धारणाधिकार वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करता येणार आहेत.

प्रकल्पबाधितांना वेळेत घरे मिळण्यासाठी समन्वय समिती

पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित वा विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांना विनाविलंब घरे मिळावीत, यासाठी महापालिका आयुक्त, एमएमआरडीए आयुक्त, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली.

मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात स्वतः महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एसआरए व इतर यंत्रणांची मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्यात येतात. परंतु, बऱ्याच वेळा सदनिकांची कमतरता आणि विविध यंत्रणांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वेळेत घरे प्राप्त होत नाहीत. या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चाही झाली होती. त्यावर प्रकल्पबाधितांना वेळेत घरे मिळण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, असे राज्य शासनाच्या वतीने आश्वासन दिले होते. प्रकल्पबाधितांना वेळेवर सदनिका प्राप्त होतील, त्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन ब्लॉक

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : रेल्वे रूळ, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड वायरच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी शुक्रवारी मध्यरात्री वसई रोड आणि वैतरणा स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर ३ तासांचा ब्लॉक घेण्यात येईल. शुक्रवारी रात्री ११.५० वाजता ते रात्री २.५० वाजेपर्यंत अप जलद मार्गावर आणि डाउन जलद मार्गावर रात्री १.४० ते पहाटे ४.४० वाजेपर्यंत असेल. गाडी क्रमांक १९१०१ विरार-भरूच मेमू १५ मिनिटे उशिराने निघेल आणि त्यामुळे विरारहून पहाटे ४.३५ वाजता नियोजित सुटण्याऐवजी पहाटे ४.५० वाजता सुटेल.

फुकट्या रेल्वे प्रवाशांवर कारवाईसाठी 'बॅटमॅन' पथक

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : लोकल प्रवास करताना रात्रीच्या वेळी तिकीट तपासनीस पथक नसल्याने, बहुसंख्य प्रवासी विनातिकीट प्रवास करीत होते. या प्रवाशांमुळे तिकीटधारक प्रवाशांचा प्रवास गैरसोयीचा होत होता. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाने रात्रीचे तिकीट तपासनीस पथक सज्ज केले. या पथकाला 'बी अवेअर टीटीई मॅनिंग अॅट नाइट' (बॅटमॅन) नाव देण्यात आले आहे.

'बॅटमॅन'द्वारे रात्रीच्या वेळी विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यात येणार असून प्रवाशांनी रात्री विनातिकीट प्रवास करू नये, असा यामागील उद्देश आहे. पश्चिम रेल्वेवरील विनातिकीट प्रवाशांची संख्या वाढल्याने रेल्वे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली होती. या विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या जात आहेत. याद्वारे विनातिकीट प्रवासी कमी होत होते. मात्र, सकाळपासून सायंकाळपर्यंत तिकीट पथकाद्वारे कडक तपासणी केली जात होती.

पथकाची गस्त सुरू

पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने 'बॅटमॅन' मोहीम सुरू केली आहे. रात्री 'बॅटमॅन' पथकाची गस्त सुरू झाली. या मोहिमेला सुरुवात झाल्यापासून अंदाजे २,३०० विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यात आले.

अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार

मुंबई : पवई येथे १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तटरक्षक दलात कार्यरत दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली. घडलेला प्रकार कोणाला सांगितल्यास पीडित मुलगी व तिच्या वडिलांना आरोपींनी ठार मारण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी पवई पोलीस ठाण्यात सामूहिक अत्याचार, धमकावणे व बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित मुलगी विद्यार्थिनी आहे. मुलीने नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी या प्रकरणी सामूहिक अत्याचार, धमकावणे व पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

मुंबईत पुन्हा पाणीकपात

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबईतील १५ टक्के पाणी कपात मागे घेतल्यानंतर आता लगेचच पुन्हा एकदा पाच टक्के पाणी कपात लागू करण्यात येणार आहे. भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात परिरक्षणविषयक कामे हाती घेण्यात आली असून, या कामांमुळे २४ एप्रिलपर्यंत मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात ५ टक्के पाणी कपात करण्यात येणार असल्याचे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे.

मुंबईत पाणीसाठा खालावल्यामुळे पाणी कपात लागू होण्याची शक्यता होती. राज्य सरकारने राखीव साठा देण्यास मान्य केल्यामुळे प्रस्तावित पाणी कपात रद्द करण्यात आली. मात्र त्यानंतर आता दुरुस्तीच्या कारणास्तव पाच टक्के पाणी कपात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सुमारे ४० दिवस पाणी कपात सुरू राहणार आहे. भांडुप संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून महानगरपालिकेच्या प्रमुख भागांना पाणीपुरवठा केला जातो. आशिया खंडातील हे सर्वात मोठे जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. भांडुप संकुलात १ हजार ९१० दशलक्ष लिटर आणि ९०० दशलक्ष लिटर पाणी शुद्धीकरण करणारी दोन युनिट्स आहेत. ९०० दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या या जलशुद्धीकरण केंद्रातील मोठ्या जलशुद्धीकरण प्रक्रिया टाक्या स्वच्छ करण्याची पावसाळ्यापूर्वीची परिरक्षण कार्यवाही सध्या हाती घेण्यात आली आहे.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd.

नोंदणीकृत आणि मुख्य कार्यालयः ८७, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
सीआयएन क्र: एल६६०००एमएच१९१९जीओआय०००५२६, आयआरडीएआय रजि. क्र.: १९०
दुरध्वनी: +९१ २२ २२७०८२६३; फॅक्स: +९१ २२ २२६५२८११
ईमेल: investors@newindia.co.in ; वेबसाइट: www.newindia.co.in

पोस्टल मतपत्रिकेची सूचना

सदस्यांना याद्वारे सूचित केले जाते की कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८ आणि कलम ११० नुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) च्या नियमन ४४ सह वाचले आहेत. विनियम, २०१५ आणि त्याअंतर्गत जारी केलेले कायदे, नियम, विनियम, परिपत्रके आणि अधिसूचना यांच्या इतर लागू तरतुदी (काही वैधानिक सुधारणा किंवा त्यामध्ये सध्याच्या काळासाठी आणि वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार पुनर्अधिनियमांसह), कंपनीकडे आहे.

ज्या सदस्यांनी त्यांचा ईमेल आयडी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट किंवा कंपनीकडे नोंदणी केली आहे त्यांना ई-व्होटिंगसाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्डसह एनएसडीएलद्वारे ईमेल पाठवला आहे; ०८ मार्च २०२४ रोजी ज्या सदस्यांची नावे सभासदांच्या नोंदणीवर/लाभार्थी मालकांच्या यादीवर दिसतील अशा सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पोस्टल बॅलटद्वारे कंपनीच्या भागधारकांची नियुक्ती करण्यासाठी कंपनीच्या सदस्यांची मान्यता मिळविण्यासाठी १) कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय ज्या राज्यात आहे ते प्रतिबिंबित करण्यासाठी कंपनीच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये दुरुस्ती, २) एओएमध्ये दुरुस्ती - कार्यकारी संचालकाच्या पदाचा समावेश करण्यासाठी आहे.

सदस्यांनी नोंद घ्यावी की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान **गुरुवार, २१ मार्च २०२४ (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:००) पासून सुरू होईल आणि शुक्रवार, १९ एप्रिल २०२४ (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५:००)** रोजी संपेल. सदस्य केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात.

पोस्टल बॅलेट/ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. एस. एन. विश्वनाथन यांची नियुक्ती केली आहे आणि त्यांना अयशस्वी झाल्यामुळे, एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन आणि कंपनीच्या भागीदार श्रीमती मालती कुमार यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.

सदस्यांच्या मतदानाचा हक्क **०८ मार्च २०२४** रोजी गणला जाईल जो कट ऑफ तारीख आहे. कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने पोस्टल बॅलेटची सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे. पोस्टल बॅलेट नोटिसची प्रत कंपनीच्या www.newindia.co.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, कृपया आमच्या www.newindia.co.in किंवा www.evoting.nsdl.com या वेबसाइटवर उपलब्ध पोस्टल मतपत्रिकेच्या सूचनेशी संलग्न असलेल्या ई-मतदानाच्या सूचना पहा.

तुमचा ईमेल आयडी आधीच कंपनी/डिपॉझिटरीमध्ये नोंदणीकृत असल्यास, ई-मतदानासाठी लॉगिन तपशील तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर पाठवले जातील. ज्या सदस्यांनी अद्याप त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी त्यांच्या DP कडे शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये ठेवल्यास आणि भौतिक स्वरूपातील शेअर्स ज्यांच्याकडे असतील तर त्यांनी मेसर्स लिंक इनटाइम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड कडे त्यांची नोंदणी करावी.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारींसाठी, सदस्यांनी श्री. महेश मसुरकर, गुंतवणूकदार संबंध, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएसमार्ग, विक्रोळी (प.), मुंबई – ४०० ०८३, यांच्याशी संपर्क साधण्याची विनंती केली आहे. दुरध्वनी क्रमांक +९१ २२ ४९१८६२७०, ईमेल आयडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in. तसेच सदस्यांनी सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल, 4था मजला, "ए" विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३, टोल फ्री क्रमांक: १८०० १०२० ९९०/१८०० २२४ ४३० या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात, ईमेल आयडी : evoting@nsdl.co.in.

न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडसाठी
एसडी/-
ज्योती रावत
कंपनी सेक्रेटरी आणि मुख्य अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
तारीख: 14 मार्च 2024

● TOWER'S CHIP PROJECT AT EVALUATION STAGE

Govt not to meddle in ISMC-Tower dispute, says Chandrasekhar

JATIN GROVER
New Delhi, March 14

WITH TOWER SEMICONDUCTOR $11-billion fab project being next in the line for approval, the government has said that it will not interfere in any ongoing legal tussle between the company and its former joint venture partner ISMC.

"Government's intent is not to consider anything. If they (Tower-ISMC) have a contractual issue, they will have to sort it out in the courts," minister of state for electronics and IT Rajeev Chandrasekhar told *FE*.

"Certainly, it's not the government that will get into adjudicating disputes between two joint venture partners, if there is any," he added.

It has been reported that ISMC Analog Fab had approached the government to not approve the semiconductor project application submitted by Tower Semiconductor.

Tower Semiconductor needs to sort out the issues in the court, MoS for electronics and IT Rajeev Chandrasekhar said

This is because Tower had earlier tied up with ISMC consortium to set up a semiconductor fab unit in the country and sought government's approval on the project.

However, later, Tower solely submitted its application with the government to seek incentives under the semiconductor scheme, officials said. This, according to ISMC, was a breach of the agreement.

In 2020, ISMC had tied up with Tower to set up a fab unit in the country and had submitted an application to the India Semiconductor Mission.

However, with the changes in the scheme structure and incentives by the government later, the companies were expected to jointly re-submit a proposal to the government. Tower later terminated the agreement with ISMC.

Tower Semiconductor's project is currently under the evaluation stage. As per the process, companies whose applications are approved are entitled for a 50% subsidy from the government on the project cost. State governments are free to further top this up with any subsidy amount they want.

₹750-cr 'blended' fund for agri startups soon

SANDIP DAS
New Delhi, March 14

TO PROMOTE INVESTMENT and bring in efficiency in the value chain of agriculture and allied sectors, the government will soon launch a dedicated fund of ₹750 crore to support and scale up operations of technology-driven agri-startups and rural enterprises.

Sources told *FE* that the agriculture ministry will roll out "blended capital support" involving the private sector to finance startups for agriculture and rural enterprises relevant for farm produce value chains, which will be managed by Nabventures, a wholly owned subsidiary of Nabard.

Out of the total ₹750 crore corpus of the fund under the "Agri-SURE" scheme, ₹250 crore each will be contributed by the agriculture ministry and Nabard. The remaining ₹250 crore will be mobilised from institutions including private investors.

Sources said the fund aimed to help scale up operations of about 85 startups in the next five years with a variable ticket size upto ₹25 crore each. A separate trust would be set up in Nabventures to register the fund with Securities and Exchange Board of India.

SCALING UP

- Of the total ₹750 cr corpus of the fund, ₹250 cr each will be contributed by the agriculture ministry and Nabard
- The aim of the fund is to promote investments in innovative, tech driven activities in agriculture

The target beneficiaries would cover those startups associated with sectors including agri-tech, food processing, animal husbandry, fisheries, supply chain management, farm mechanisation and biotechnology, according to officials. The modalities prior to launching of Agri-SURE is currently being worked out.

The aim of the fund would be to provide investments to startups unable to scale up their operations for want of access to equity and debt instruments to create new forward and backward linkages in the rural ecosystem.

Finance minister Nirmala Sitharaman in her budget for 2022-23 had announced a fund with blended capital, raised under the co-investment model, will be facilitated through Nabard. "This is to finance startups for agriculture and rural enterprise, relevant for farm produce value chain," she had said.

Officials said that the aim of the fund is to promote investments in innovative, technology driven, high-risk, high-impact activities in agriculture and allied areas."This would also provide funding support to start-ups engaged in infrastructure development and employment generation in rural areas," a source said.

Currently, the agriculture ministry is also implementing 'Innovation and Agri-Entrepreneurship Development' programme under Rashtriya Krishi Vikas Yojana since 2018-19.

JSW Energy arm bags 700 MW SECI project

JSW NEO ENERGY, a wholly owned subsidiary of JSW Energy, has received a letter of award for a 700 MW inter-state transmission system (ISTS) solar project from the Solar Energy Corporation of India (SECI).

The project was awarded through a tariff-based competitive bid that Seci invited for setting up of 1,500 MW ISTS-connected solar power projects. The company's current installed generation capacity is 7.2 GW, which it expects to go up to 9.8 GW by 2024. With the award of the latest 700 MW solar project, the company's total locked-in generation capacity has increased to 11.7 GW, with solar capacity being 2.1 GW.

Additionally, the firm has 3.4 GWh of locked-in energy storage capacity, including the battery energy storage system.

—FE BUREAU

Early start to wheat procurement drive

SANDIP DAS
New Delhi, March 14

THE GOVERNMENT'S WHEAT procurement drive for 2024-25 rabi marketing season (April-June) has commenced with Food Corporation of India (FCI) purchasing grain from farmers in Rajasthan.

Officials said that this is the earliest ever commencement of MSP operations in any year where FCI purchased around 20 tonne of wheat in Jhalawar district, Rajasthan on Wednesday.

Although the wheat purchase usually commences from April 1 for the marketing season, this year the government had urged states to begin MSP operations of wheat early.

The grain procurement target for the 2024-25 season is around 30–32 million tonne (MT) against 26.2 MT purchased from the farmers under MSP operations last season.

Higher purchase is expected to bolster the FCI's stock. At present, FCI has a wheat stock of 8.62 MT, lowest since 2016.

MSP OPS BEGIN

- The grain procurement target for the 2024-25 season is around 30–32 MT against 26.2 MT purchased from the farmers
- At present, FCI has a wheat stock of 8.62 MT, lowest since 2016

"Wheat arrivals in mandis would gradually pick up pace by the end of the month in Rajasthan and Madhya Pradesh," a food ministry official said. Meanwhile, Madhya Pradesh, the second biggest contributor to the central pool wheat stock after Punjab, will commence operations to buy grain at minimum support price (MSP) in Khargone and Ujjain districts from Friday. The state is aiming to purchase 10 MT of wheat this season from farmers.

"We have registered 1.5 million farmers for procurement so far and this number is bound to increase as we have extended farmers' registration till end of the month," Smita Bharadwaj, additional chief secretary, food, civil supplies and consumer affairs, told *FE*.

GAIL to set up retail LNG biz with ₹650-crore investment

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, March 14

STATE-RUN NATURAL gas company GAIL India is looking to foray into retail LNG (liquefied natural gas) aiming to increase its use as a transportation fuel with a potential investment of ₹650 crore, the firm said on Thursday.

Highlighting the potential of LNG business to grow substantially, the company, in an exchange filing, said that it plans to set up LNG dispensing stations across golden quadrilateral or major national highways, aspiring to acquire more than 50% market share in the next 5-6 years.

"This will help GAIL in the retail LNG sector, leading to an increase in natural gas portfolio. By converting transport fuel from diesel to LNG, reduction in carbon footprint is envisaged," the company said.

GAIL's new business plan comes at a time when the government is aiming to increase the share of natural gas in the energy mix to 15% from present 6% by 2030 enabling it to realise the goal of net-zero by 2070.

"Proposed line of business investment is strategic in nature which relates to exploring opportunity-based investment for the development of LNG dispensing infrastructures & last mile connectivity along golden quadrilateral/national highways, mining areas as alternative to diesel meant to serve customers with fuel having lower carbon footprints," it said.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd.

Regd. & Head Office: 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001
CIN No.: L66000MH1919GOI000526, IRDA Reg No : 190
Tel: +91 22 22708263; Fax: +91 22 22652811
Email: investors@newindia.co.in; Website: www.newindia.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has:.

Sent an email through NSDL, along with the login ID and password to the members for e-voting who have registered their email id's or Depository Participant(s) or with the Company; to all the members whose name appears on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 08th March, 2024 for voting through electronic mode for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot.

for seeking approval of Members of the Company for appointment of 1. Amendment to Memorandum of Association of Company so as to reflect the state in which the Registered Office of the Company is situated. 2. Amendment to AOA - To include position of Executive Director

Members are requested to note that the voting, through electronic mode shall commence from **Thursday, 21st March, 2024 (9:00 a.m. IST) and end on Friday, 19th April, 2024 (5:00 p.m. IST).** The members can opt for only electronic mode of voting.

The Board of Directors have appointed Mr. S. N. Viswanathan and failing him, Ms. Malati Kumar, partner of S. N. Ananthasubramanian & Co., as the Scrutinizer for conducting the postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting rights of Members shall be reckoned as on **08th March, 2024** which is the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.newindia.co.in.

In case of any query relating to voting by electronic means, please refer to instructions for e-voting annexed to the Notice for Postal ballot available on our website www.newindia.co.in or www.evoting.nsdl.com .

If your email ID is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting will be sent on your registered email address. Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with M/s Link Intime (India) Pvt Ltd in case the shares are held by them in physical form.

For any queries/grievances relating to e-voting, members are requested to contact Mr.Mahesh Masurkar, Investor Relations, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (W), Mumbai – 400083, Tel No. +91 22 49186270, email id : rnt.helpdesk@linkintime.co.in. Members can also contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, "A" Wing, Trade World , Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Toll free no: 1800 1020 990/1800 224 430, email id : evoting@nsdl.co.in.

For THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED
Sd/-
JYOTI RAWAT
COMPANY SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Place: Mumbai
Date: 14th March, 2024